अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि दूरदर्शन द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रसारण के लिए पृथक चैनल चलाया जाए, जिससे छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों, गायकों और निर्माताओं का भी विकास हो सके।

Demand to provide employment to families/locals displaced due to NCL, Singrauli and NTPC, Sonbhadra projects

श्री राम शकल (नाम निर्देशित) : महोदय, भारत सरकार की अनेक परियोजनाएं देश के विभिन्न स्थानों पर चल रही हैं। इनमें अनेकों परिवार विस्थापित हुए हैं, जिनको अभी तक विभागों द्वारा मुआवज़ा एवं नौकरी नहीं दी गई है, जिसके कारण स्थानीय युवा रोज़गार से वंचित हैं। सरकार को चाहिए कि नीति बना कर विस्थापितों एवं स्थानीय युवकों के लिए नौकरी आरक्षित करे, विशेषकर एनसीएल, सिंगरौली एवं एनटीपीसी, सोनभद्र में स्थानीय युवक एवं विस्थापित परिवार नौकरी न मिलने के कारण दुखी हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि परियोजनाओं में विस्थापित परिवारों एवं स्थानीय युवकों को रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु तत्काल नीति तैयार की जाए एवं उनके लिए रोज़गार सुनिश्चित किया जाए।

एनसीएल, सिंगरौली एवं एनटीपीसी, सोनभद्र में विस्थापित परिवारों एवं स्थानीय युवकों को नौकरी देने हेतु तत्काल निर्णय लिया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following Special Mentions are deemed to be laid on the Table.

Demand for the construction of Kanpur outer ring road to resolve the problem of traffic jam

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयों को समेटे कानपुर में लगने वाला जाम सप्ताह के सातों दिन निरंतर बढ़ता जा रहा है। कानपुर शहर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25ए, 2ए, 91 व 86 गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से शहर में जाम और अधिक होता है। इस समस्या के समाधान हेतु कानपुर आउटर रिंग रोड बनने की प्रक्रिया वर्ष 2012 से चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में इतना अधिक विलंब हो चुका है कि लोग कानपुर के जाम से पलायन करने लगे हैं।

कानपुर में प्रस्तावित आउटर रिंग रोड बन जाए तो जाम समाप्त जो जाए। प्रावधानों के तहत भूमि अध्याप्ति के कार्यों में वित्तीय सहभागिता की जानी थी। यद्यपि इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अंशधारिता कितनी होगी, यह निर्धारित नहीं है। कानपुर आउटर रिंग रोड के संदर्भ में राज्य सरकार ने लखनऊ रिंग रोड प्रोजेक्ट की भांति कानपुर के प्रोजेक्ट के भू अध्याप्ति के कार्यों में 10 प्रतिशत की वित्तीय सहभागिता का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा है।

महोदय, आपसे आग्रह है कि आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कानपुर आउटर रिंग रोड के लिए अंशधारिता को अविलम्ब जारी करें, जिससे सड़क निर्माण हो सके और कानपुर में लगने वाला जाम समाप्त हो, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Demand for approval of the proposal for development in the vicinity of Defence establishments in Maharashtra

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, the proposal dated 03.03.2017 sent by the hon. Chief Minister of Maharashtra to the hon. Defence Minister, Government of India regarding development permission in the vicinity of Defence establishments is still awaiting response from Government of India despite the lapse of sufficient time and the matter being of the public importance.

Therefore, through this august House, I urge that urgent and suitable directions may please be issued to the Government of India to consider the aforesaid proposal and reply to the Maharashtra Government at the earliest.

Demand for execution of Jharia Master Plan including BCCL Coal Mining area through a Central Agency

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): महोदय, बीसीसीएल कोयला खनन क्षेत्र के अन्तर्गत झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग और भू-धंसान को नियंत्रित करने तथा इससे प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिए झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी गयी है, जिसे 12 वर्षों की अवधि के पश्चात् इसी वर्ष, अर्थात् 2021 में पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। भारत सरकार ने इसके लिए पर्याप्त निधि का आवंटन भी किया है। झरिया मास्टर प्लान का क्रियान्वयन झारखंड राज्य सरकार के प्राधिकार झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जरेडा) द्वारा किया जा रहा है, जिसकी प्रगति अत्यन्त धीमी है। विगत 12 वर्षों के अनुभव को देखते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किसी केन्द्रीय एजेंसी को सौंपना और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के साथ अभिषरण (कन्वर्जेन्स) कर एक नया शहर विकसित करना श्रेयस्कर होगा। मैं इस विषय को सदन में विशेष उल्लेख के माध्यम से रखना चाहता हूँ।